प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण : भारतीय अनुभव

सांभवी ढींगरा, अर्पिता अग्रवाल, और स्नेहल एस. हेरवाडकर^ द्वारा

भारत में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) का उपयोग अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद क्षेत्रों को ऋण देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप उपकरण के रूप में किया गया है। मार्च 2006 से मार्च 2023 तक तिमाही बैंक-स्तरीय डेटा का लाभ उठाते हुए, अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों की शुरूआत ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण में वृद्धि की है। विश्लेषण आगे बताता है कि पीएसएल अपनी आस्ति गुणवत्ता के प्रति उत्तरदायी है और उच्च पीएसएल वृद्धि बैंकों की समग्र आस्ति गुणवत्ता में सुधार करती है।

परिचय

वाणिज्यिक बैंकिंग भारत की वित्तीय प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका दायरा और पहुंच लगातार बढ़ रही है। अनौपचारिक ऋण संस्थानों की व्यापकता और बैंकिंग सेवाओं तक असमान पहुंच ने वित्तीय समावेशन नीतियों की शुरुआत करना आवश्यक बना दिया। भारत में, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) समावेशन उद्देश्य को आगे बढ़ाने की समग्र संरचना और योजना के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से, अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जो आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं और रोजगार-प्रधान हैं, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं (आरबीआई, 2007)। इनमें मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई), आवास, निर्यात, शिक्षा और कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए ऋण शामिल हैं। भारत में पीएसएल दिशा-निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन किया गया है ताकि उन्हें उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकता-प्राप्तओं के साथ जोड़ा जा सके और समावेशी विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके।

इस आलेख का उद्देश्य भारत में पीएसएल कार्यक्रम के रुझानों की जांच करना है, साथ ही इसके प्रमुख चालकों का मूल्यांकन करना है। यह बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर पीएसएल के प्रभाव का भी आकलन करता है। आलेख का शेष भाग इस प्रकार व्यवस्थित है। खंड II निर्देशित ऋण देने के औचित्य और अंतर-देशीय अनुभव पर साहित्य का दृष्टि प्रदान करता है। खंड III भारत में पीएसएल के विकास और अब तक के प्रदर्शन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। खंड IV अनुभवजन्य विश्लेषणों के साथ अनुसंधान पद्धति प्रस्तुत करता है, जबकि खंड V आलेख का समापन किया गया है।

II. साहित्य की समीक्षा

उच्च लेन-देन लागत और सूचना विषमता की व्यापकता अपेक्षाकृत जोखिमपूर्ण लेकिन आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों और उधारकर्ताओं तक ऋण प्रवाह को सीमित कर सकती है। अपेक्षित परियोजना विवरणी के बारे में पूरी जानकारी के अभाव में, बैंक अपने ऋण देने के निर्णयों को अवलोकनीय जोखिम विशेषताओं और/या अच्छे संपार्श्विक की उपलब्धता पर आधारित करते हैं, जिससे पारंपरिक रूप से व्यवहार्य उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह जारी रहता है। ऐसी परियोजनाओं को कम लाभ पहुँचाने का यह जोखिम, जिनकी ऋण तक पहुँच पहले से ही सीमित है, सरकारों को पीएसएल-प्रकार के कार्यक्रम लागू करने के लिए प्रेरित कर सकता है (मुंद्रा, 2017)।

कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रावधान को सीमित करने वाली असममित सूचना की समस्या और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। कृषि रोजगार पैदा करके, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके और गरीबी को कम करके आर्थिक संवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में। हालांकि, वर्षा पर उनकी भारी निर्भरता और बार-बार होने वाले जलवायु झटकों के कारण कृषि उपज और कीमतों में अंतर्निहित अनिश्चितता को देखते हुए, किसान उधारकर्ताओं को अक्सर ऋण तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ सकता है (कैलोमिरिस और हिमेलबर्ग, 1993)। औपचारिक ऋण के अभाव में, उन्हें निर्देशित ऋण कार्यक्रमों के तहत लाना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है (चक्रवर्ती, 2012)।

इसी तरह, लघु उद्योग अक्सर 'अनौपचारिक' प्रकृति के होते हैं और पर्याप्त दस्तावेज़ों की कमी उन्हें वित्तपोषित करने में एक बड़ी बाधा है। ये उद्योग, जिनमें आमतौर पर कम पूंजी-

^ लेखक, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) से हैं। डॉ. टी. गोपीनाथ, नवजोत कौर, शिबी मथाई, शालिनी जैन, पर्यवेक्षण विभाग और आरबीआई बुलेटिन संपादकीय समिति से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

उत्पादन अनुपात होता है और श्रम गहन होते हैं, जरूरी नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों के पसंदीदा ग्राहकों में से हों और इसलिए, ऋण की कमी हो सकती है। ऐसे उद्योगों को ऋण देना विशेष रूप से श्रम-अधिशेष विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में फायदेमंद है, क्योंकि यह रोजगार पैदा करता है और आय असमानता को कम करता है (कोहली, 1997)।

निर्देशित उधार की प्रभावकारिता पर अलग-अलग विचार हैं, विशेष रूप से इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के संबंध में। उदाहरण के लिए, 1984-86 में तमिलनाडु में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि राष्ट्रीयकृत बैंक, जिन्होंने कृषि को भारी मात्रा में उधार दिया, सरकारी ऋण योजनाओं में पर्याप्त रूप से भाग लिया और कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के उधारकर्ताओं को महत्वपूर्ण मात्रा में निर्देशित किया, उनकी वसूली दर सबसे अधिक थी (नारायण, 1992)। पीएसएल बैंकों की अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपातों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है (गौर और महापात्रा, 2020)। दूसरी ओर, कुछ अध्ययनों के अनुसार, चार भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी श्रम और प्रशासनिक लागत अनारक्षित क्षेत्र में ऋण देने की तुलना में अधिक थी, और ऐसे ऋणों ने बैंकों के एनपीए में आनुपातिक रूप से अधिक योगदान दिया (बनर्जी और डुफ्लो, 2000; बनर्जी और डुफ्लो, 2014)।

प्राथमिकता-प्राप्त ऋण के संभावित व्यापक आर्थिक प्रभावों ने मौजूदा साहित्य में कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ शर्तों के तहत, निर्देशित ऋण कार्यक्रमों के रूप में सरकारी हस्तक्षेप न केवल वित्तीय विकास की शुरुआत करेगा, बल्कि संस्थानों की स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी प्रदान करेगा (चक्रवर्ती और अन्य, 2019)। हालांकि, एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि छोटी फर्मों ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण तक पहुंच पाने के लिए अपने विस्तार का त्याग किया (भुए और अन्य, 2019)।

रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर और सामाजिक समानता को बढ़ावा देकर, प्राथमिकता-प्राप्त वाले क्षेत्रों के लिए निर्देशित ऋण गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालता है, जिससे संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है (गौर और मोहपात्रा, 2020)। इस तरह के कार्यक्रम आय असमानता और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता को कम करने के कल्याण उद्देश्यों को पूरा करने के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन (फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को, 2014) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि मुहम्मद यूनुस (1987) ने टिप्पणी की, यदि पीएसएल का कार्यान्वयन दोषपूर्ण है और एनपीए अधिक है, तो *"किसी को विफलता के लिए प्राप्तकर्ता देश के लोगों को दोष देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए; बल्कि किसी को उस ऋण संस्थान के डिजाइनर को दोष देना चाहिए जो काम करने में विफल रहा।"*

ऋण निर्देशन के तंत्र विभिन्न रूप लेते हैं, जैसे ब्याज सब्सिडी, ब्याज दर सीमा, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष ऋण, सरकारी गारंटी, बैंकों के लिए ऋण कोटा, विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) के माध्यम से ऋण देना या इन तरीकों का संयोजन। कई देशों में, विशेष रूप से ईएमई में पीएसएल का कोई न कोई रूप मौजूद है। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया अपने कुल पोर्टफोलियो के 20 प्रतिशत के कोटा के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को प्राथमिकता-प्राप्त ऋण देता है (आईएलओ, 2019)। मलेशिया और वियतनाम ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के लिए ब्याज दर छूट लागू की (फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को, 2014)।

प्रत्यक्ष ऋण की नीति पूर्वी एशियाई देशों में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक थी (विश्व बैंक, 1993)। जापान विकास बैंक ने निजी बैंकों से वृद्धिशील ऋण देने, नई फर्मों को ऋण की बेहतर पहुँच प्रदान करने और युद्ध के बाद के जापान में नए निवेश को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (होरियुची और सुई, 1993)। कोरिया में, सरकार के नेतृत्व में ऋण की दिशा ने व्यापक बाजार खामियों को दूर करने और नए उधारों को निवेश में बदलने में मदद की, जिससे आगे की आर्थिक वृद्धि हुई (चो और हेलमैन, 1993; वर्नर, 2002)। फ्रांसीसी ऋण गारंटी कार्यक्रम ने नव निर्मित फर्मों के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और लक्षित फर्मों को व्यवस्थित रूप से अधिक बाहरी वित्त जुटाने, कम ब्याज खर्च का भुगतान करने और अन्य समान फर्मों की तुलना में उच्च विकास दर का आनंद लेने में सक्षम बनाया (लेलार्ज और अन्य, 2010)।

अमेरिका में, जबकि निर्देशित ऋण कार्यक्रम लक्षित समूह को ऋण बढ़ाने में सफल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उस समूह द्वारा निवेश में वृद्धि करें (श्वार्ट्ज, 1992)। कुछ मामलों में, अकुशल कार्यान्वयन ने संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देने के बजाय आय असमानता को भी बढ़ाया है,

जैसे कोस्टा रिका में, जहां सब्सिडी वाले ऋण ने लक्षित समूह के बजाय आबादी के सबसे धनी 10 प्रतिशत लोगों की आय में वृद्धि की (वोगेल, 1984)। कई देशों में, ये कार्यक्रम उच्च एनपीए, कम लाभप्रदता और लक्ष्यों को पूरा करने में शामिल उच्च परिवर्तनीय लागतों के साथ-साथ नैतिक जोखिम संबंधी चिंताओं के मामले में बैंकिंग उद्योग के लिए विशेष रूप से महंगे साबित हुए। इंडोनेशिया में, बैंकिंग प्रणाली के एसएमई ऋण पोर्टफोलियो ने समग्र पोर्टफोलियो की तुलना में निम्न आस्ति गुणवत्ता प्रदर्शित की (फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को, 2014)।

दक्षिण कोरिया और जापान में, निर्देशित ऋण कार्यक्रमों को आम तौर पर प्रभावी ढंग से लागू किया गया माना जाता है, जिनकी सफलता के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। इन देशों में हस्तक्षेपकारी नीतियों को उचित संस्थागत तंत्र द्वारा पूरक बनाया गया है। जापान में, एक बार जब किसी फर्म को ऋण तक प्राथमिकता पहुंच मिल जाती है, तो उन्हें पीएसएल के तहत आगे उधार लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है और नए उधारकर्ताओं को ऋण दिया जाता है। कोरिया में, यदि लाभार्थियों द्वारा प्रदर्शन मानकों को पूरा नहीं किया जाता है, तो ऋण वापस ले लिया जाता है या नया ऋण देने से मना कर दिया जाता है। सख्त प्रदर्शन मानकों के साथ-साथ प्रभावी निगरानी तंत्र ने इन कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित की।

संक्षेप में, उपलब्ध साहित्य निर्देशित ऋण कार्यक्रमों की प्रभावकारिता पर कई तरह के विचार प्रस्तुत करता है। आलेख में किया गया विश्लेषण निम्नलिखित तरीकों से मौजूदा साहित्य में योगदान देता है। सबसे पहले, जबकि भारतीय संदर्भ में पहले के अधिकांश शोधपत्र या तो सैद्धांतिक या केस स्टडी थे, यह आलेख अनुभवजन्य रूप से पीएसएल के चालकों का मूल्यांकन करता है। दूसरा, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर पीएसएल के प्रभाव पर साहित्य बहुत कम है, खासकर भारत के लिए; यह आलेख इस कमी को पूरा करता है। तीसरा, यह बैंक-स्तरीय तिमाही पर्यवेक्षी डेटा का उपयोग करता है, जो विश्लेषण में अधिक विस्तृत जानकारी जोड़ता है।

III. भारत में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण

III.1 इतिहास और उद्भव

1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से भारत में प्राथमिकता-प्राप्त प्राप्त क्षेत्र को उधार देना, ऋण नियंत्रण नीतियों का मुख्य आधार रहा है। 1972 में, प्राथमिकता-प्राप्त प्राप्त क्षेत्र और उस योग्य क्षेत्रों का विवरण, रिज़र्व बैंक के एक अनौपचारिक अध्ययन समूह की सिफारिशों के आधार पर औपचारिक रूप दिया गया था, और 1974 में इसके लिए कुल ऋण का 33.33 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे 1979 तक हासिल किया जाना था। 1980 में लक्ष्य को और बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया, साथ ही कृषि और कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए विशिष्ट उप-लक्ष्य भी निर्धारित किए गए, जिन्हें 1985 तक हासिल किया जाना था। तब से, विभिन्न प्रकार के बैंकों पर अलग-अलग प्रयोज्यता, ऋण की मात्रा, लक्षित क्षेत्र और उप-लक्ष्य, और बैंकों द्वारा कमी के उपचार के संदर्भ में दिशानिर्देशों में और परिवर्तन हुए हैं। अप्रैल 2007 से, पीएसएल आवश्यकता को बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)[1] या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईओबीई) के समतुल्य ऋण के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट किया जा रहा है, जो भी अधिक हो।

अपने वर्तमान स्वरूप में, पीएसएल दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू वाणिज्यिक बैंकों [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को छोड़कर] और विदेशी बैंकों (एफबी) को अपने एएनबीसी या सीईओबीई का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देना आवश्यक है।[2] कुल लक्ष्य में से, 18 प्रतिशत कृषि के लिए निर्धारित है [लघु और सीमांत किसानों (एसएमएफ)[3] के लिए 10 प्रतिशत], सूक्ष्म उद्यमों के लिए

[1] एएनबीसी = बैंक ऋण + ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत बकाया जमाराशि तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) तथा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) लिमिटेड के पास प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य/उप-लक्ष्य की प्राप्ति न होने के एवज में अन्य पात्र निधियां + बकाया पीएसएलसी + प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में माने जाने योग्य अन्य निवेश + परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) श्रेणियों में बांड/डिबेंचर - आरबीआई तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थानों के पास पुनर्भुनाए गए बिल - अवसंरचना तथा किफायती आवास के लिए दीर्घकालिक बांड जारी करने पर छूट हेतु पात्र राशि - वृद्धिशील विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफसीएनआर (बी)]/अनिवासी बाह्य (एनआरई) जमाराशियों के विरुद्ध भारत में दिए गए अग्रिम, जो नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)/एसएलआर आवश्यकताओं से छूट के लिए अर्ह हैं - भारत सरकार द्वारा जारी पुनर्पूंजीकरण बांडों में पीएसबी द्वारा किए गए निवेश - लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 के अंतर्गत एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत अर्जित और रखी गई प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य।

[2] 20 से कम शाखाओं वाले वित्तीय बैंकों को एएनबीसी या सीईओबीई का 40 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देना होगा, जिसमें से 32 प्रतिशत निर्यात के लिए और 8 प्रतिशत से कम अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिए नहीं हो सकता है। आरआरबी और एसएफबी को अपने एएनबीसी या सीईओबीई का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देना होगा।

[3] 4 सितंबर, 2020 को जारी रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, एसएमएफ के लिए उप-लक्ष्य 2020-21 में 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 2021-22 में 9 प्रतिशत, 2022-23 में 9.5 प्रतिशत और 2023-24 में 10 प्रतिशत कर दिया गया।

7.5 प्रतिशत और कमज़ोर वर्गों के लिए 12 प्रतिशत।[4] पीएसएल का दायरा धीरे-धीरे उन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए व्यापक किया गया है, जिन्होंने समकालीन समय में प्रमुखता हासिल की है। तदनुसार, सामाजिक बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित ऋण को 2015 में पीएसएल में शामिल किया गया था।

कोविड-19 के कारण प्राथमिकताओं पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में निवेश करने का महत्व सामने आया। नवीनतम पीएसएल दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूल, पेयजल और स्वच्छता सुविधाएँ स्थापित करने के लिए प्रति उधारकर्ता 5 करोड़ रुपये तक के ऋण और टियर II से टियर VI केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ (*'आयुष्मान भारत'* के तहत) बनाने के लिए प्रति उधारकर्ता 10 करोड़ रुपये तक के ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।[5]

III.2 लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की प्राप्ति

अपने जोखिम प्रोफाइल और मौजूदा ग्राहकों के आधार पर, बैंक अप्रत्यक्ष मार्गों का सहारा ले सकते हैं, जैसे अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों का प्रतिभूतिकरण, साथ ही प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा, पीएसएल प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) अप्रैल 2016 में पेश किए गए थे, जैसा कि वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर रघुराम राजन समिति (2009) ने सिफारिश की थी, ताकि बैंकों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत श्रेणियों को अधिशेष उधार देने को प्रोत्साहित करते हुए कमी की स्थिति में पीएसएल लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। यह पीएसएलसी में व्यापार करने वाले बैंकों को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और अधिक कुशलता से ऋण वितरित करने का लाभ भी प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत चार श्रेणियों के लिए पीएसएलसी की ट्रेडिंग की अनुमति है - कृषि, एसएमएफ, सूक्ष्म उद्यम और सामान्य। जिन बैंकों के पास अभी भी कमी है, उन्हें आरआईडीएफ और नाबार्ड/एनएचबी/सिडबी/मुद्रा लिमिटेड के साथ अन्य फंड में योगदान करना आवश्यक है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण आम तौर पर विभिन्न समयावधियों और बैंक समूहों में 40 प्रतिशत से अधिक रहा है, तथा इसका सटीक अनुपात, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक की समग्र व्यावसायिक रणनीति, पहुंच, ऐसे ऋणों की आस्ति गुणवत्ता और उनकी विशेषज्ञता पर निर्भर करता है (चार्ट 1)।

चार्ट 1: पीएसएल लक्ष्य उपलब्धि

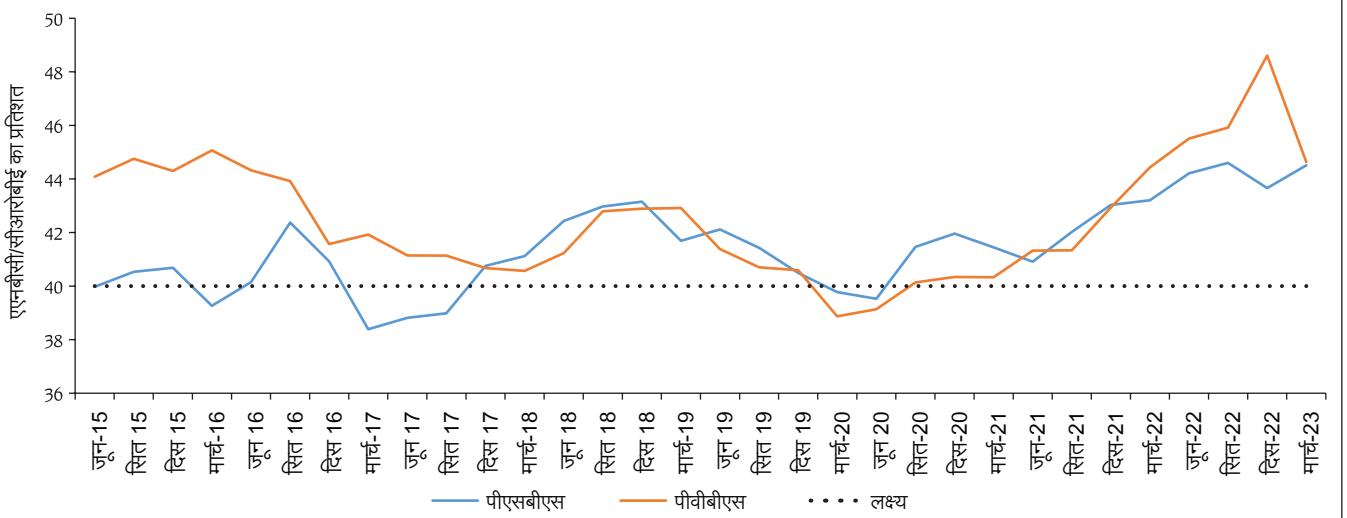

टिप्पणी : वार्षिक पीएसएल लक्ष्य प्राप्ति को चार तिमाहियों के औसत के रूप में मापा जाता है। इस प्रकार, चार्ट में प्रत्येक तिमाही में लक्ष्य से विचलन को कमी के रूप में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

स्रोत: आरबीआई

[4] कमजोर वर्गों के लिए उप-लक्ष्य को 2020-21 में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 2021-22 में 11 प्रतिशत, 2022-23 में 11.5 प्रतिशत तथा 2023-24 में 12 प्रतिशत कर दिया गया।

[5] नवीनतम दिशानिर्देश https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=11959 पर देखे जा सकते हैं

चार्ट 2 : पीएसएल उप लक्ष्य उपलब्धि

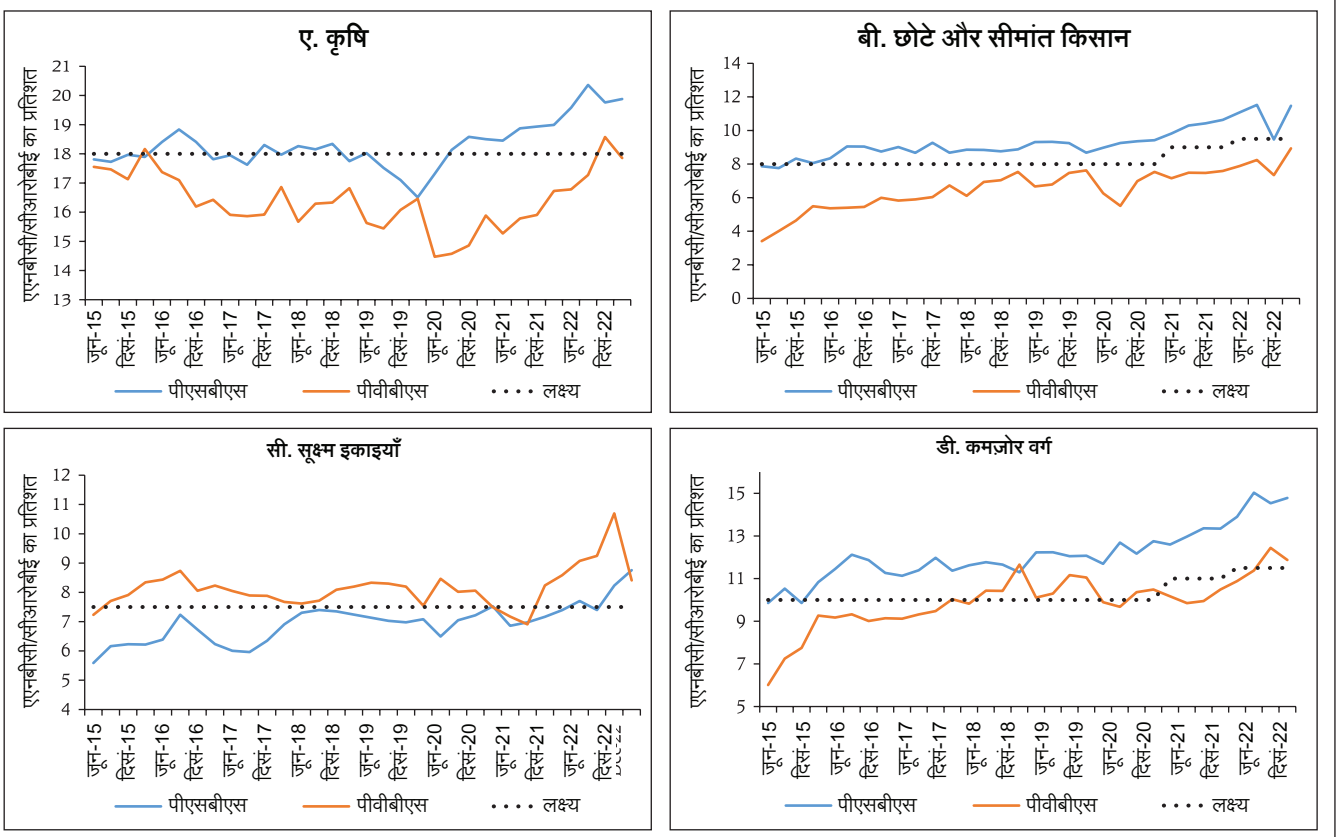

टिप्पणी : वार्षिक पीएसएल उप-लक्ष्य उपलब्धि को चार तिमाहियों के औसत के रूप में मापा जाता है। इस प्रकार, चार्ट में प्रत्येक तिमाही में उप-लक्ष्य से विचलन को कमी के रूप में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।
स्रोत: आरबीआई

कृषि के मामले में, पीएसबी ने अधिकांश अवसरों पर 18 प्रतिशत का अपना लक्ष्य पूरा किया है; निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी), जो पहले लगातार लक्ष्य से पीछे रह जाते थे, हाल के वर्षों में लक्ष्य के अनुरूप हो गए हैं। दूसरी ओर, पीवीबी ने सूक्ष्म उद्यमों को अपने एएनबीसी या सीईओबीई का 7.5 प्रतिशत उधार देने के उप-लक्ष्य को प्राप्त करने में पीएसबी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। पीएसबी और पीवीबी दोनों ने कमजोर वर्गों को उधार देने के अपने लक्ष्य को पूरा किया है, जिसमें पीएसबी अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों से आगे हैं (चार्ट 2)।

IV. साक्ष्य आधारित विश्लेषण

साक्ष्य आधारित विश्लेषण दो भागों में विभाजित है। सबसे पहले, बैंकों को अपने एएनबीसी/सीईओबीई का 40 प्रतिशत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को आबंटित करने की आवश्यकता वाले सामान्य विनियामकीय अधिदेश के बावजूद, विभिन्न बैंकों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताएं मौजूद हैं। अध्ययन का यह भाग उन संभावित कारकों की जांच करता है जो बैंकों के पीएसएल की सीमा को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा, अध्ययन बैंकों की समग्र आस्ति गुणवत्ता पर पीएसएल के प्रभाव की जांच करता है।

IV.1 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के चालक

बैंकों द्वारा पीएसएल को प्रभावित करने वाले कारकों को निर्धारित करने के लिए एक अभ्यास निश्चित प्रभाव पैनल प्रतिगमन मॉडल का उपयोग करके किया जाता है। मार्च 2006 से मार्च 2023 की अवधि के लिए पीएसबी और पीवीबी के तिमाही डेटा का उपयोग किया जाता है। सभी डेटा रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी विवरणी से प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित पैनल प्रतिगमन समीकरण का अनुमान लगाया गया है:

$$PSL\ share_{it} = \beta_1\ PSL\ share_{it-1} + \beta_2\ PSL\ GNPA\ ratio_{it-1} + \beta_3\ Branches\ to\ assets\ ratio_{it} + \beta_4\ log(assets)_{it-1} + \beta_5\ PSLC\ dummy_t + \beta_6\ March\ dummy_t + \alpha_y + \vartheta_i + \varepsilon_{it} \quad (I)$$

जहां $PSL\ share_{it}$ समय t पर बैंक i के लिए सकल ऋणों और अग्रिमों[6] में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों का हिस्सा है, $PSL\ share_{it-1}$, *PSL share,* के एक अवधि के विलंबित मूल्य को संदर्भित करता है, $PSLGNPAratio_{it-1}$ प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के लिए विलंबित आस्ति गुणवत्ता सूचक है, $branches\ to\ asset\ ratio_{it}$ बैंक की पहुंच का एक प्रॉक्सी है, और $log(assets)_{it-1}$ बैंक के आकार का एक संकेतक है। *PSLCdummy* पीएसएलसी की शुरूआत के प्रभाव को पकड़ने के लिए जून 2016 से शुरू होने वाले सभी तिमाहियों के लिए मूल्य 1 लेता है। चूंकि पीएसएल की कमी की गणना हर वित्तीय वर्ष के अंत में डेटा पर आधारित होती है, इसलिए $Mrchdummy_{it}$ पेश किया जाता है, जो मार्च[7] को समाप्त होने वाली सभी तिमाहियों के लिए मूल्य 1 लेता है α_y वर्ष के निश्चित प्रभाव हैं, ϑ_i बैंक के निश्चित प्रभाव[8] हैं, और ε बैंक स्तर पर क्लस्टर की गई मानक त्रुटियाँ हैं और विषमता के लिए समायोजित की गई हैं। तीन वैकल्पिक विनिर्देशों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें आश्रित चर कुल ऋण में संपूर्ण पीएसएल हिस्सा, कुल ऋण में कृषि के लिए पीएसएल और कुल ऋण में MSEs[9] के लिए पीएसएल हैं।

साक्ष्य आधारित आकलन के परिणाम बताते हैं कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पोर्टफोलियो की आस्ति गुणवत्ता बैंकों के पीएसएल हिस्से को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि पीएसएल विनियामक आवश्यकताओं द्वारा अनिवार्य है, लेकिन बैंक इन ऋणों को विस्तारित करते समय सामान्य जोखिम-वापसी ट्रेड-ऑफ को ध्यान में रखते हैं।

बैंक शाखाओं-से-संपत्ति अनुपात द्वारा मापी गई व्यापक बैंक पहुंच, प्राथमिकता-प्राप्त वाले क्षेत्र को वितरित ऋणों के उच्च हिस्से के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है। अधिक भौतिक उपस्थिति वाले बैंक जमीनी स्तर पर प्राथमिकता-प्राप्त वाले ऋण देने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। कृषि और एमएसई पीएसएल विनिर्देशों में, क्रमशः ग्रामीण शाखाओं-से-संपत्ति अनुपात और शहरी शाखाओं-से-संपत्ति अनुपात का उपयोग व्याख्यात्मक चर के रूप में किया गया है। परिणाम संकेत देते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बड़े शाखा नेटवर्क वाले बैंक अपने ऋणों का बड़ा हिस्सा प्राथमिकता-प्राप्त वाले एमएसई को देते हैं। हालांकि, उच्च ग्रामीण उपस्थिति वाले बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त वाले क्षेत्र के कृषि ऋणों के परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हैं, संभवतः इन क्षेत्रों में आरआरबी, एसएफबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों की उपस्थिति को दर्शाते हैं, जिनके पास कृषि वित्तपोषण में अधिक विशेषज्ञता है। बैंक के आकार का पीएसएल हिस्से पर महत्वपूर्ण और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सारणी 1: पीएसएल शेयर के निर्धारक

चर	पीएसएल शेयर	कृषि पीएसएल शेयर	एमएसई पीएसएल शेयर
	(1)	(2)	(3)
पीएसएल शेयर (एल1)	0.678*** (0.0435)		
कृषि पीएसएल शेयर (एल1)		0.810*** (0.0462)	
एमएसई पीएसएल शेयर (एल1)			0.628*** (0.0486)
पीएसएल जीएनपीए अनुपात (एल1)	-0.225*** (0.0609)		
कृषि पीएसएल जीएनपीए अनुपात (एल1)		-0.0971*** (0.0201)	
एमएसई पीएसएल जीएनपीए अनुपात (एल1)			-0.200*** (0.0386)
शाखाओं से आस्तियां	0.436* (0.251)		
ग्रामीण शाखाओं से आस्तियां		-0.0572 (0.253)	
शहरी शाखाओं से आस्तियां			1.340*** (0.458)
लॉग (आस्तियां) (एल1)	-1.453** (0.533)	-0.636*** (0.220)	-0.580* (0.292)
पीएसएलसी डमी	1.606** (0.658)	-0.139 (0.390)	1.603*** (0.425)
मार्च डमी	1.465*** (0.346)	0.471** (0.184)	1.149*** (0.164)
स्थिर	25.83*** (6.717)	9.049*** (2.436)	8.411** (3.324)
अवलोकन	2,162	2,162	2,161
समायोजित आर-स्क्वेयर्ड	0.626	0.762	0.698
बैंकों की संख्या	33	33	33
बैंक निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ
वर्ष निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बैंक स्तर पर मजबूत मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
2. ***, ** और * 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।

स्रोत: लेखकों द्वारा गणना।

[6] आदर्श रूप से, अनुमान के लिए एएनबीसी/सीईओबीई में पीएसएल की हिस्सेदारी पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, एएनबीसी/सीईओबीई डेटा की निरंतर उपलब्धता की कमी के कारण, इसके बजाय सकल ऋण और अग्रिम का उपयोग किया जाता है। यहां पीएसएल में बैंकों द्वारा लक्षित क्षेत्रों को सीधे वितरित किए गए ऋण के साथ-साथ अनुभाग III.2 में उल्लिखित लक्ष्य प्राप्ति के अन्य उपाय शामिल हैं।

[7] वार्षिक पीएसएल लक्ष्य प्राप्ति को चार तिमाहियों के औसत के रूप में मापा जाता है। बैंक अपने पीएसएल लक्ष्य को वार्षिक आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वे हर तिमाही में ऐसा न करें।

[8] निश्चित प्रभाव और यादृच्छिक प्रभाव के बीच उपयुक्त मॉडल विनिर्देश निर्धारित करने के लिए, हौसमैन परीक्षण आयोजित किया गया था, और परिणामों ने संकेत दिया कि निश्चित प्रभाव मॉडल अधिक उपयुक्त था।

[9] प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं, और उप-लक्ष्य केवल सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए निर्धारित है। हालाँकि, इस विश्लेषण के लिए, डेटा सीमाओं के कारण केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों को ही शामिल किया गया है।

पीएसएलसी की शुरुआत के बाद से बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में पीएसएल की हिस्सेदारी बढ़ गई है, जिससे कुछ बैंकों को विशिष्ट पीएसएल खंडों में अपनी जगह बनाने में मदद मिली है। डेटा से पता चलता है कि ऐसे बैंक अपने विशेष खंडों को विनियामक न्यूनतम से अधिक ऋण देते हैं और इन अतिरिक्त उपलब्धियों को पीएसएलसी में बदल देते हैं, जिसका वे प्रीमियम पर व्यापार करते हैं। पीएसएलसी डमी का सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण और सकारात्मक गुणांक दर्शाता है कि इसके शुरू होने से बैंकों को अपने समग्र और एमएसई पीएसएल शेयर में सुधार करने में मदद मिली है। मार्च तिमाही में पीएसएल शेयर के शिखर को भी मॉडल में शामिल किया गया है।

IV.2 पीएसएल की आस्ति गुणवत्ता

ऐतिहासिक रूप से, प्राथमिकता-प्राप्त वाले क्षेत्रों से प्राप्त ऋणों का एनपीए उनके गैर-प्राथमिकता-प्राप्त वाले क्षेत्रों के समकक्षों की तुलना में अधिक रहा है, जिनमें से अधिकांश पीएसबी के खातों में रहे हैं। हालांकि, 2015 में यह प्रवृत्ति उलट गई, आंशिक रूप से आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के बाद एनपीए की बेहतर पहचान के कारण (जॉन और अन्य, 2016)[10] [चार्ट 3]।

आँकड़े आधारित साक्ष्य बताते हैं कि बैंकों के जीएनपीए बैंक विशिष्ट और समष्टि-वित्त (चव्हाण और गंबाकोर्टा, 2016) पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा , हमारे अनुमान का फोकस यह जांचना है कि बैंकों के पीएसएल का उनकी समग्र आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। इसके लिए, पिछले उपखंड में इस्तेमाल किए गए समान डेटासेट पर पैनल रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करके एक अभ्यास किया गया था।

$$GNPA\ \ Ratio_{it} = \beta_1\ \ PriorityLoanGrowth_{it-1} + \beta_2\, AQR_t + \beta_3 X_{it-1} + \alpha_y + \vartheta_i + \varepsilon_{it} \quad \text{(II)}$$

जहाँ आश्रित चर समय t पर बैंक i का जीएनपीए अनुपात है। $PriorityLoanGrowth_{it-1}$ एक अवधि है जो बैंक के पीएसएल में वर्ष-दर-वर्ष पिछड़ी हुई वृद्धि है। AQR_t संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के लिए एक डमी चर है जो सितंबर 2015 और मार्च 2018 के बीच की तिमाहियों के लिए 1 और अन्यथा 0 लेता है। X_{it-1} बैंक-स्तरीय नियंत्रण हैं, जिसमें बैंक समूह के लिए डमी, आस्तियों पर विलंबित विवरणी और बैंक आकार का पिछड़ा हुआ लॉग (ऋण और जमा का योग) शामिल है। α_y वर्ष के निश्चित-प्रभाव हैं, ϑ_i बैंक के निश्चित प्रभाव हैं[11], और ε_{it} बैंक स्तर पर क्लस्टर की गई मानक त्रुटियाँ हैं और विषमता के लिए समायोजित की गई हैं।

चार्ट 3 : आस्ति गुणवत्ता: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण बनाम गैर-प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

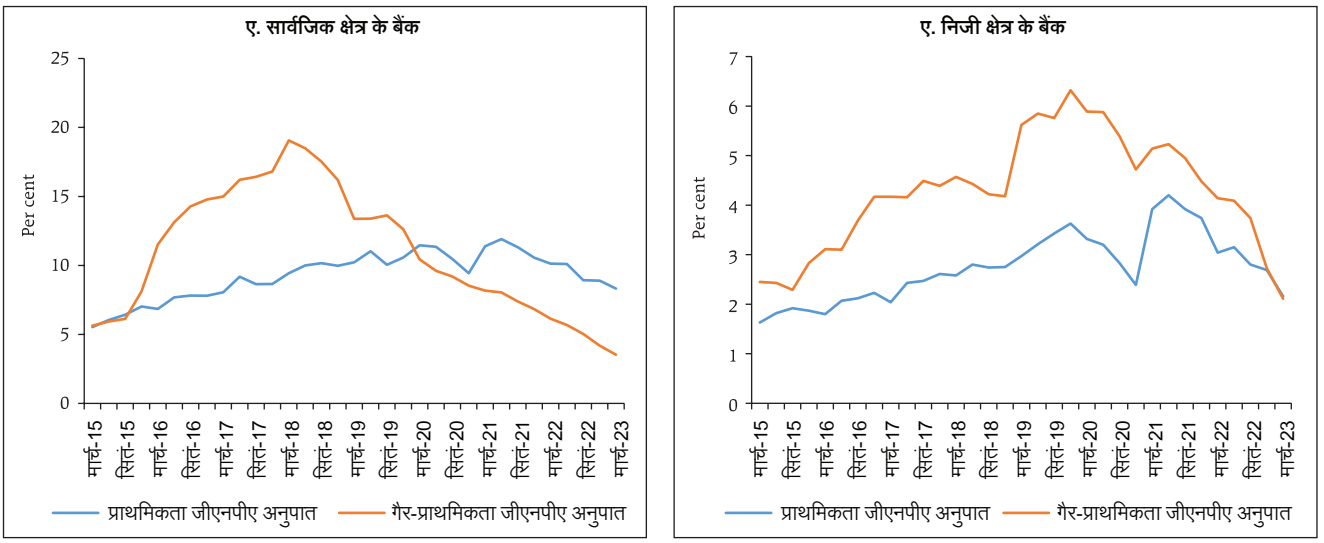

स्रोत: ऑफ-साइट रर्टिन (घरेलू परिचालन), आरबीआई।

[10] जुलाई 2015 में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) का उद्देश्य बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करना तथा उनकी पारदर्शिता में सुधार लाना था, साथ ही उनके एनपीए प्रावधानों को बढ़ाना था।

[11] निश्चित प्रभाव और यादृच्छिक प्रभाव के बीच उपयुक्त मॉडल विनिर्देश निर्धारित करने के लिए, हौसमैन परीक्षण आयोजित किया गया था, और परिणामों ने संकेत दिया कि निश्चित प्रभाव मॉडल अधिक उपयुक्त था।

सारणी 2: बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर पीएसएल वृद्धि का प्रभाव

चर	आश्रित चर : जीएनपीए अनुपात			
	(1)	(2)	(3)	(4)
प्राथमिकता अग्रिम वृद्धि (L1)	-0.0254***	-0.0483***	-0.0210***	-0.0226***
	(0.00457)	(0.00841)	(0.00382)	(0.00455)
एक्यूआर डमी	0.757***	0.539***	0.742***	9.751***
	(0.185)	(0.153)	(0.180)	(1.667)
संपत्तियों पर प्रतिफल (L1)	-3.188***		-3.187***	-3.238***
	(0.327)		(0.308)	(0.319)
लॉग (आकार) (L1)	-1.860***		-3.338***	-3.401***
	(0.383)		(0.684)	(0.711)
बैंक समूह डमी	5.200***			
	(1.264)			
स्थिर	24.82***	4.205***	42.68***	
	(3.864)	(0.597)	(7.253)	
अवलोकन	2,030	2,030	2,030	
बैंक निश्चित प्रभाव	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
वर्ष निश्चित प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
समय निश्चित प्रभाव	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
समायोजित R-स्क्वायर	0.534#	0.465	0.713	0.716
बैंकों की संख्या	33	33	33	33

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिये गए आंकड़े बैंक स्तर पर बड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।

2. ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।

3. #: समग्र आर-स्क्वायर की रिपोर्ट की गई है।

स्रोत : लेखकों द्वारा गणना।

जैसा कि अपेक्षित था, प्रतिगमन से प्राप्त प्राथमिक परिणाम दर्शाते हैं कि एक्यूआर अवधि के दौरान जीएनपीए अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में अग्रिमों में उच्च वृद्धि ने बैंकों के जीएनपीए अनुपात को कम कर दिया है।

सारणी 2 के कॉलम (1) में, यह पाया गया है कि बैंक समूह डमी का गुणांक, जो पीएसबी के लिए 1 और पीवीबी के लिए 0 का मान लेता है, सकारात्मक और महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्ययन अवधि के दौरान पीवीबी की तुलना में पीएसबी का जीएनपीए अनुपात अधिक था। कॉलम (2) में, बैंक के निश्चित प्रभाव जोड़े गए हैं और उनके समावेश के परिणाम मजबूत बने हुए हैं। कॉलम (3) में, अन्य बैंक-स्तरीय नियंत्रण जोड़े गए हैं और यह पाया गया है कि बैंकों की उच्च लाभप्रदता और बड़े आकार के साथ आस्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा, कॉलम (4) में, सभी बहिर्जात समय-भिन्न कारकों के लिए नियंत्रण में समय-निश्चित प्रभाव जोड़ने के बाद भी, परिणाम मजबूत बने हुए हैं।

V. निष्कर्ष

पीएसएल जैसी ऋण योजनाएं जरूरतमंद क्षेत्रों को औपचारिक ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए हैं। निर्देशित ऋण पर देशांतर साहित्य बैंकों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में अनिर्णय में हैं। एक दृष्टिकोण से, इस तरह के ऋण तभी सफल हो सकते हैं जब उचित संस्थागत तंत्र, सख्त प्रदर्शन मानकों और नीतिगत ढांचे द्वारा पूरक हों। विरोधी दृष्टिकोण के अनुसार, ये ऋण, विनियामकीय बाध्यताओं के कारण, बैंकों के व्यावसायिक हितों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं और संभावित रूप से उनकी समग्र आस्ति गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर सवाल उठ सकते हैं। यह आलेख इन तर्कों का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन करता है।

मार्च 2006 से मार्च 2023 तक बैंक-स्तरीय पीएसएल डेटा का उपयोग करते हुए, अध्ययन में पाया गया है कि बैंकों के कुल ऋण पोर्टफोलियो में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों की हिस्सेदारी, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे ऋणों की आस्ति गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसके अलावा, पीएसएलसी की शुरूआत ने बैंकों को कुछ प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में एक जगह बनाने में मदद करने और परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों में ऋण देने में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साक्ष्य आधारित विश्लेषण यह भी बताता है कि पीएसएल में उच्च वृद्धि बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट से जुड़ी नहीं है।

संदर्भ

Banerjee, A., and Duflo, E. (2000). Efficiency of Lending Operations and the Impact of Priority Sector Regulations. *MIMEO, MIT.*

Banerjee, A., and Duflo, E. (2014). Do Firms Want to Borrow More? Testing Credit Constraints using a Directed Lending Program. *The Review of Economic Studies*, 81(2), 572–607. doi: 10.1093/restud/rdt046

Bhue, G., Prabhala, N., and Tantri, P. (2019). Can Small Business Lending Programs Disincentivize Growth? Evidence from India's Priority Sector Lending Program. *Indian School of Business.*

Calomiris, C. W., and Himmelberg, C. P. (1993). Directed Credit Programs for Agriculture and Industry: Arguments from Theory and Fact. *The World Bank Economic Review*, 7(1), 113-138. https://doi.org/10.1093/wber/7.suppl_1.113

Chakrabarty, K. C. (2012). *Revised Guidelines on Priority Sector Lending: Rationale and Logic.* Retrieved from https://www.bis.org/review/r120906b.pdf

Chakrabarti, D., Sethi, P., and Bhattacharjee, S. (2019). Directed Credit, Financial Development and Financial Structure: Theory and Evidence. *Applied Economics*, 51(16), 1711-1729. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1528338

Chavan, P., and Gambacorta, L. (2016). Bank Lending and Loan Quality: The Case of India. *BIS Working Papers*, 595. https://www.bis.org/publ/work595.pdf

Cho, Y. J., and Hellman, T. (1993). The Government's Role in Japanese and Korean Credit Markets: A New Institutional Economics Perspective. *The World Bank, Policy Research Working Papers Series*, 1190. https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/1190.html

Federal Reserve Bank of San Francisco. (2014). *Priority Sector Lending in Asia.* Retrieved from https://www.frbsf.org/banking/wp-content/uploads/sites/5/Asia-Focus-Priority-Sector-Lending-in-Asia-September-2014.pdf

Gaur, D., and Mohapatra, D. R. (2020). The Nexus of Economic Growth, Priority Sector Lending and Non-Performing Assets: Case of Indian Banking Sector. *South Asian Journal of Business Studies.* https://www.emerald.com/insight/2398-628X.htm

Horiuchi, A., and Sui, Q.-Y. (1993). The Influence of the Japan Development Bank Loans on Corporate Investment Behaviour. *Journal of the Japanese and International Economies*, 7(4), 441-465. doi:10.1006/jjie.1993.1025

ILO. (2019). Financing Small Businesses in Indonesia: Challenges and Opportunities. International Labour Organization.

John, J., Mitra, A.K., Raj, J., and Rath, D.P. (2016). Asset Quality and Monetary Transmission in India. *Reserve Bank of India Occasional Papers*, 37(1and2). Available at https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/RBIOP37020520185C7D2C48AFA9427993B773BD194D95A2.PDF

Kohli, R. (1997). Directed Credit and Financial Reform. *Economic and Political Weekly*, 32(42), 2667-2676. http://www.jstor.com/stable/4405977

Lelarge, C., Sraer, D., and Thesmar, D. (2010). Entrepreneurship and Credit Constraints: Evidence from a French Loan Guarantee Program. *International Differences in Entrepreneurship*, 243 - 273. https://ideas.repec.org/s/nbr/nberch.html

Mundra, S. S. (2017). *Priority Sector Lending – Status, Issues and Future Agenda.* Retrieved from https://www.bis.org/review/r170724f.pdf

Narayana, D. (1992). Institutional Credit for Rural Development: Proper Risk-Management of Group Lending? *Economic and Political Weekly*, 27(39), A122-A127. https://www.jstor.org/stable/4398941

RBI. (2007). *Master Circular- Lending to Priority Sector.* Available at https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/78389.pdf

Schwarz, A. M. (1992). How Effective are Directed Credit Policies in the US? *The World Bank, Policy*

Research Working Paper Series, 1019. https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/1019.html

Vogel, R. C. (1984). The Effect of Subsidised Agricultural Credit on Income Distribution in Costa Rica. In D. W. Adams, D. H. Graham, and J. D. Pishke (Eds.), *Undermining Rural Development with Cheap Credit.* New York: Routledge.

Werner, R. A. (2002). A Reconsideration of the Rationale for Bank Centered Economic Systems and the Effectiveness of Directed Credit Policies in the Light of Japanese Evidence. *Japanese Economy*, 30(3), 3-45. https://doi.org/10.2753/JES1097-203X30033

World Bank. (1993). *The East Asian Miracle.* Available at https://documents1.worldbank.org/curated/en/975081468244550798/pdf/multi-page.pdf

Yunus, M. (1987). The Poor as the Engine of Development. *The Washington Quarterly*, 10(4), 139–145. https://doi.org/10.1080/01636608709477624